बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 106

पर्याप्त सलाह, अमल जरूरी

सरकार कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन की योजना बना रही है। इसकी कोई खास तुक समझ में नहीं आ रही। इस विषय पर तमाम पैनल पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट इस संकटग्रस्त क्षेत्र को मजबूत बनाने संबंधी लगभग हर सलाह दे चुकी है। इन पैनलों में सबसे उल्लेखनीय हैं एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय किसान आयोग, शांता कुमार की अध्यक्षता वाली खाद्य क्षेत्र सुधार समिति और अशोक दलवई के नेतृत्व वाली किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी अधिकार प्राप्त समिति। इसके अलावा सरकार का अपना थिंक टैंक नीति आयोग भी कृषि क्षेत्र के कुछ अहम हिस्सों में सुधार के लिए जरूरी और उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत कर चुका है। हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य लोगों ने नीति आयोग की संचालन परिषद में प्रस्तावित समिति के संदर्भ में जो बातें कहीं उन पर भी उक्त दस्तावेजों में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। ये मुद्दे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाने, लॉजिस्टिक्स, मूल्यवर्धन, विपणन सहायता, सिंचाई, खासतौर पर ड्रिप और अन्य प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई तथा उन विधायी बदलावों से संबंधित हैं जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में सुधार ला सकते हैं।

स्वामीनाथन आयोग ने वर्ष 2006 में पांच हिस्सों में जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें कृषि विकास कार्यक्रमों में आमूलचूल बदलाव लाते हुए उत्पादन बढ़ाने के बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया था। सरकार को इस सलाह का महत्त्व समझने और इस दिशा में काम करने में एक दशक से अधिक वक्त लग गया। हालांकि समिति की कई अन्य समान समझदारी भरी अनुशंसाओं पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। दलवई समिति की 14 हिस्सों में जारी रिपोर्ट का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। इस रिपोर्ट का एक हिस्सा कृषि क्षेत्र के ढांचागत सुधारों और संचालन ढांचे से संबंधित था। इस दिशा में ताजातरीन कवायद सितंबर 2018 में आई रिपोर्ट है जो मौजूदा कृषि संकट की दृष्टि से सर्वाधिक प्रासंगिक है। नीति आयोग द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर सरकार वाकई कृषि क्षेत्र में सुधार लाने को लेकर इतनी तत्पर है तो उसे इन पर ध्यान देते हुए जरूरी सुझावों का चयन करना होगा और समयबद्ध तरीके से उनका अनुपालन करना होगा।

उस लिहाज से देखा जाए तो इस सच की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कृषि से जुड़े मसलों में केंद्र के हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि संविधान के मुताबिक यह राज्य का विषय है। केंद्र बिना राज्यों के सहयोग के कुछ खास नहीं कर सकता है। अक्सर राज्यों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता। केंद्र की चुनिंदा पहल मसलन कृषि विपणन सुधार, भूमि की पट्टा प्रणाली और अनुबंधित कृषि को विनियमित करने जैसी छिटपुट सफलताओं में इस बात की अहम भूमिका रही है। राज्यों के कानूनों में जरूरी सुधारों के गाइड के रूप में काम करने वाले आदर्श विधेयक वांछित परिणाम दे पाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि स्वामीनाथन आयोग ने कृषि को संविधान की राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखने की बात कही है। इससे केंद्र कृषि क्षेत्र में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा जबकि राज्य सरकारों के अधिकारों में भी कोई कमी नहीं आएगी। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन की सहायता से शिक्षा, वन एवं वन्यजीव संरक्षण जैसे पांच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। जब तक केंद्र सरकार सांविधिक उपायों से या दबाव बनाकर राज्य सरकारों को मंच पर नहीं लाती है, कृषि क्षेत्र में सुधार होता नजर नहीं आता।

बिनय सिन्हा

सरकार के सामने अनेक वृहद आर्थिक चुनौतियां

अहम वृहद आर्थिक कारक नकारात्मक संकेत दे रहे हैं, इसलिए सामान्य कदम उठाना विकल्प नहीं है। बता रहे हैं **शंकर आचार्य**

हाल में चुनी गई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपना पहला बजट तैयार कर रही है, लेकिन उसके सामने कई वृहद आर्थिक चुनौतियां हैं। हर अहम वृहद आर्थिक संकेतक (मुख्य रूप से महंगाई को छोड़कर) कमजोरी के संकेत दे रहे हैं।

■ हाल में जारी आधिकारिक आंकड़े दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में जीडीपी वृद्धि घटकर 5.8 फीसदी पर आ गई, जो 20 तिमाहियों में सबसे धीमी है। इस तरह पूरे साल की वृद्धि का अनुमान घटकर 6.8 फीसदी पर आ गया है, जो पिछले पांच साल में सबसे कम है। इससे तेज मंदी के उन संकेतों की पुष्टि हो गई है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कारोबारी आंकड़े, वाहन एवं उपभोक्ता वस्तु बिक्री, पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडीसेज (पीएमआई), कंपनी आमदनी जैसे तात्कालिक संकेतक दे रहे थे।

■ वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में वास्तविक निवेश वृद्धि घटकर 3.6 फीसदी पर आ गई। विनिर्माण वृद्धि घटकर 3.1 फीसदी और कृषि वृद्धि ऋणात्मक 0.1 फीसदी रह गई। निजी निवेश स्थिर बना हुआ है।

■ उसी दिन सरकार ने आखिरकार एनएसएसओ की 2017-18 की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी। इसने यह पुष्टि की कि देश में रोजगार की स्थिति सात दशकों में सबसे खराब है और काम करने की उम्र वाली आबादी में से आधी से भी कम काम कर रही है या काम ढूंढ रही है। (श्रम बल भागीदारी दर या एलएफपीआर)। महिलाओं की एलएफपीआर महज 23 फीसदी थी, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। युवा महिलाओं की एलएफपीआर भी महज 16 फीसदी थी। श्रम बल में शामिल लोगों की बेरोजगारी भी 6.1 फीसदी थी, जो 45 वर्ष में सबसे अधिक है। बेरोजगारी की दर युवाओं में बहुत अधिक थी। यह शहरी महिलाओं में 27 फीसदी तक थी।

■ देश के बाहरी वित्तीय संतुलन पर दबाव है। भुगतान संतुलन में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 2.5 फीसदी के ऊंचे स्तर पर है। चिंताजनक बात यह है कि सबसे अधिक आमदनी वाला वस्तु निर्यात 2011-12 से स्थिर बना हुआ है। इससे जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 2018-19 में घटकर 12 फीसदी पर आ गई है, जो सात साल पहले 17 फीसदी थी।

■ देश के राजकोषीय संतुलन पर भी दबाव है। केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त रूप से घाटा जीडीपी के करीब सात फीसदी पर है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी की जरूरत (पीएसबीआर) जीडीपी की करीब नौ फीसदी है। पीएसबीआर ज्यादा प्रासंगिक मापदंड बन गया है क्योंकि राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकारी खर्च (और संबंधित उधारी जरूरतों) को भारतीय खाद्य निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को स्थानांतरित करने का रुझान तेज हुआ है। सरकार का जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात जीडीपी के करीब 70 फीसदी के असहज स्तर पर पहुंच गया है और संभावित देनदारियां बढ़ रही हैं।

वित्तीय क्षेत्र कई वर्षों से 'दोहरी बैलेंस शीट' की समस्या के कारण अत्यधिक दबाव में है। दोहरी बैलेंस शीट की समस्या के तहत वाणिज्यिक बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) ऊंचे स्तर पर हैं और कंपनियों और लोगों पर बकाया ऋण देनदारी का भारी बोझ है। पिछले साल से पहले तक सुधार के कुछ संकेत नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले साल सितंबर में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) में संकट खड़ा हो गया। इसका असर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अन्य क्षेत्रों पर असर पड़ रहा है।

■ आखिर में ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बड़े व्यापार युद्धों का वैश्विक आर्थिक माहौल भारत में जल्द आर्थिक सुधार के लिए अनुकूल नहीं है।

इसलिए वृद्धि, निवेश एवं रोजगार को फिर से बढ़ाने, समष्टि आर्थिक संतुलनों में सुधार और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है। इन सभी को बजट से दुरुस्त किया जा सकता है या कुछ बाहरी कदम उठाने होंगे? आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े स्तर के नीतिगत उपायों के बारे में विचार करते हैं।

राजकोषीय नीति : राजकोषीय घाटा और पीएसबीआर दोनों ऊंचे स्तरों पर हैं, इसलिए अतिरिक्त राजकोषीय प्रोत्साहनों के लिए और गुंजाइश नहीं है। इनमें पूरी घरेलू वित्तीय बचत खप जाती हैं। अगर इनमें और बढ़ोतरी हुई तो निजी निवेश खत्म हो जाएगा और मध्यम एवं लंबी अवधि के ऋणों पर ब्याज दरें और बढ़ जाएंगी, जो पहले ही काफी ऊंचे स्तरों पर हैं। व्यय की वर्तमान प्रतिबद्धताओं, हाल में राजस्व में अप्रत्याशित कमी और बढ़ते भुगतान बकाये को मद्देनजर रखते हुए केंद्र के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 फीसदी पर रखना चुनौतीपूर्ण होगा। आदर्श स्थिति तो यह होगी कि इसमें कुछ कमी आए। प्रक्रियागत सुधारों और दर समायोजन के जरिये वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व को मजबूत करना और प्रत्यक्ष करों के आधार को विस्तृत बनाना महत्त्वपूर्ण होगा।

मौद्रिक नीति : आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार तीन बार दर में कटौती के जरिये रीपो दर में कुल 0.75 फीसदी कमी की है, जिसमें से महज 0.2 फीसदी लाभ नए बैंक ऋणों को पहुंचाया गया है। इसमें चौंकाने वाली कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार की बड़े पैमाने पर उधारी ले रही है, जिससे लंबी अवधि की दरें ऊंची बनी हुई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादातर बैंकों पर ऊंचे एनपीए के नकारात्मक असर, इनसे जुड़ी ऊंची लागत एवं जोखिमों और एनबीएफसी क्षेत्र के दबाव से नीतिगत दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। इससे निवेश पर भी सकारात्मक असर कम हो रहा है। असल में सरकार की अधिक उधारी और वित्त क्षेत्र पर दबाव होने से मौद्रिक नीति के वांछित असर नहीं दिख रहे हैं। मौद्रिक नीति के प्रभावी बनने से पहले इन चीजों का समाधान करना होगा।

व्यापार एवं विनिमय दर पॉलिसी : सरकार को ऊंचे सीमा शुल्क और रुपये के अधिमूल्यन के पिछले दो वर्षों के रुझानों को तत्काल पलटने की जरूरत है। सरकार को क्षेत्रीय कारोबारी समझौतों, विशेष रूप से क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर जोर देने की जरूरत है। केवल तभी जीडीपी में घटते निर्यात के हिस्से के रुझान को पलटा जा सकेगा, भारत की वैश्विक मूल्य शृंखला में भागीदारी बढ़ेगी, आयात के विकल्पों को प्रभावी रूप से प्रोत्साहित किया जा सकेगा और वृद्धि को मजबूत किया जा सकेगा।

सुधारों पर जोर : निजी निवेश और वृद्धि को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि बहुप्रतीक्षित सुधारों को लागू किया जाए। हालांकि इसका फल मिलने में समय लगेगा, लेकिन किसी पैकेज की स्पष्ट एवं विश्वसनीय घोषणाओं से कारोबारी जगत का आत्मविश्वास सुधरेगा और लघु अवधि में निवेश में इजाफा होगा। इन अहम सुधारों में ये शामिल हैं। श्रम कानूनों एवं नियमनों में बदलाव करना ताकि उन्हें आसान बनाया जा सके और संगठित क्षेत्र में नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सके। अन्य सुधारों में गैर-कृषि उपयोग की खातिर आसानी से भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाना, कृषि विपणन सुधारों को आगे बढ़ाना, महंगी एवं कीमतों को प्रभावित करने वाली सरकारी खाद्यान्न खरीद एवं वितरण प्रणाली में बदलाव और ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता की प्रक्रिया को मजबूत करना आदि शामिल हैं।

कारोबार को आसान बनाना : इस दिशा में काफी कुछ किया गया है। लेकिन काफी कुछ किया जाना बाकी है, विशेष रूप से निर्यात एवं आयात के संबंध में। इसमें से कुछ नया नहीं है। लेकिन ये वृद्धि, निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। हमेशा की तरह कारोबारों पर कम वृद्धि, कमजोर रोजगार, वित्तीय स्थिति बिगड़ने और अस्थिर तेल कीमतों एवं बाहरी पूंजी आवक से प्रभावित होने के जोखिम बरकरार हैं।

(लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर हैं और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

कम लागत वाली तरंग ऊर्जा में संभावनाएं ज्यादा

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

नवीकरणीय ऊर्जा के जिन स्वरूपों का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है उनमें से एक है जल तरंग ऊर्जा। जल तरंगों से बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर इसे बिजली में बदलकर इसका लाभ उठाया जा सके तो बहुत फायदा हो सकता है। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के उलट यह हर मौसम में पूरी तरह उपलब्ध रहती है।

हालांकि यह विचार काफी समय से हमारे सामने है लेकिन इस पर बहुत अधिक शोध नहीं किया गया है। जल तरंगों के इस्तेमाल का पहला प्रयास सन 1799 में हुआ जब फ्रांसीसी विद्वान पियरे सिमॉन गिरार्ड ने पानी का एक टर्बाइन बनाया और उसके पेटेंट के लिए आवेदन दिया। ऐसे आधुनिक प्रयोग सन 1940 के दशक में योशिओ मासुदा ने किए। मासुदा जापानी नौसेना में कमांडर थे। उन्होंने एक उपकरण तैयार किया जो दोलन करने वाले पानी के कॉलम (ओडब्ल्यूसी) का प्रयोग करता था।

ओडब्ल्यूसी की अवधारणा एकदम सामान्य है। मासुदा ने जो उपकरण बनाया था वह पानी पर बहने वाला एक चैंबर था। इस चैंबर में हवा का एक कॉलम था और नीचे पानी की ओर एक छेद था। जल तरंगों के कारण उपकरण के अंदर पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था जिससे एयर कॉलम में संकुचन उत्पन्न होता था। इससे एक पिस्टन संचालित होता था और बिजली बनती थी। वर्तमान में भी इस उपकरण के कुछ बेहतर स्वरूपों का उपयोग आम है।

कई अन्य बेहतरीन अवधारणाओं का भी इस्तेमाल किया गया है। साल्टर डक एक और ऐसा उपकरण है जो एक पेंडुलम का इस्तेमाल करता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रॉलिक रैम का प्रयोग किया जाता है जो एक दोहरे वॉल्व या मल्टी वॉल्व में दबाव उत्पन्न करके काम करती है। जब तरंग चरम पर होती है तब यह पानी पर दबाव बनाकर उसे रैम में भेजती है। एक वॉल्व बंद होता है और दूसरा खुलता है। इससे ऐसा उच्च दाब बनता है जो पानी को गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकूल धकेलता है और टर्बाइन को संचालित करता है। तरंग के लौटने के साथ ही दबाव कम होता है और दूसरा वॉल्व बंद हो जाता है। इस बीच पहला वॉल्व खुल जाता है और टर्बाइन एक बार फिर से चल पड़ती है। कुछ अन्य जनरेटर गति का इस्तेमाल करते हैं। तरंगों की गति का इस्तेमाल करके उसे विद्युत शक्ति में बदला जाता है। एक अन्य अवधारणा है पानी में डूबे हुए कारपेट कन्वर्टर की। यह रबर जैसे लचीले पदार्थों से बना होता है। यह कारपेट तरंग की गति के साथ झुकता है। इस गति का इस्तेमाल पिस्टन को संचालित करने में किया जाता है।

ओवरटॉपर्स के रूप में संबद्ध रैंप्स का प्रयोग किया जाता है जो तैरते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के रूप में काम करते हैं। जब कोई तरंग अपने चरम पर होती है तब पानी रैंप पर चढ़ता है और जलाशय भर जाता है। इसके बाद हाइड्रो टर्बाइन की सहायता से पानी निकाल दिया जाता है।

तरंग ऊर्जा स्थानीय भूगोल, हवा से जुड़े कारकों और विभिन्न तरंगों के आपसी संबंधों के गणित पर निर्भर करती है। ऐसे कई कंप्यूटर मॉडल हैं जो इन चरों का अध्ययन करके यह अनुमान लगाते हैं कि आदर्श स्तर पर कितनी तरंग ऊर्जा निरंतर मिलती रहेगी। इसका बिजली में रूपांतरण आश्चर्यजनक रूप से ऊंचे स्तर पर हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ उपकरणों के माध्यम से तो 80 से 90 फीसदी तरंग ऊर्जा को बिजली में बदला जा सकता है। हालांकि तरंग ऊर्जा कई कारणों से बेहद महंगी भी है। तरंगों से बिजली प्राप्त करने के लिए जटिल अभियांत्रिकी का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा इसे समुद्री मार्ग से कहीं उपयोगी स्थान पर ले जाना भी आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी काफी रखरखाव की आवश्यकता होती है। समुद्र का पानी खारा होता है और खराब मौसम भी कई बार उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है।

हमेशा की तरह नई तकनीक से जुड़ा होने के कारण पर्यावरण को लेकर भी कई गंभीर चिंताएं हैं। तरंग परिवर्तक समुद्री पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। पानी के भीतर आवाज की तीव्रता बढ़ जाती है और वह अधिक तेज गति से गुजरता है। हवा के उलट समुद्री जल कहीं बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है इसलिए परिवर्तक और पारेषण व्यवस्था को बेहद सावधानीपूर्वक बनाना होता है। इसका भलीभांति इंसुलेटेड होना आवश्यक है ताकि किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जा सके।

यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज समेत दुनिया के तमाम देशों में जल तरंग से बनने वाली ऊर्जा को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। इन देशों में इसके संयंत्र भी स्थापित हैं। देश की इकलौती ऐसी प्रायोगिक परियोजना केरल के विझिनजम में चलाई गई जिसे आईआईटी मद्रास संचालित करता था। इसे कुछ वर्ष पहले बंद कर दिया गया। सौर, पवन या जीवाश्म ईंधन के उलट तरंग ऊर्जा को लेकर देश में कोई मिशन भी नहीं चल रहा है।

अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने वेव्स टु वाटर नामक दिलचस्प प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें इनाम के रूप में 25 लाख डॉलर की राशि दी जानी है। प्रतिस्पर्धियों को केवल समुद्री लहरों को बिजली के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करके समुद्री पानी से स्वच्छ जल निर्मित करना है। उन्हें अपनी परियोजना की अवधारणा और तकनीकी डिजाइन प्रस्तुत करना होगा तथा एक नमूना बनाकर खुली प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन करना होगा।

अब तक तरंग ऊर्जा काफी महंगी है और कई तकनीक ऐसी हैं जो अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं। जब तक तकनीक स्थिर नहीं होती है तब तक लागत ज्यादा बनी रहेगी। अगर तकनीक उन्नत होती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो तरंग ऊर्जा सस्ती भी होगी और पवन या सौर ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय भी होगी।

भारत और शेष विश्व के लिए इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। हमारे यहां 7,500 किलोमीटर की तट रेखा है, कई द्वीप हैं। हम 60 गीगावॉट तक तरंग ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का अनुमान है कि उसकी बिजली जरूरत का 65 फीसदी इसके जरिये पूरा हो सकता है।

कानाफूसी

दीदी की दवा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को चिकित्सकों के साथ मुलाकात के दौरान काफी सौजन्य दिखाया। इस मुलाकात के बाद सरकार और चिकित्सकों के बीच का गतिरोध समाप्त हो गया। इस मुलाकात बैठक की शुरुआत होने के पहले ही ममता ने चिकित्सकों के पास संदेश भेजा कि वह बैठक का सीधा प्रसारण किए जाने की उनकी मांग को स्वीकार कर रही हैं। मुलाकात शुरू होने के बाद जब 'दीदी' ने वादा किया कि अगर चिकित्सकों की सुरक्षा से समझौता हुआ तो वह कड़ा कदम उठाएंगी तो चिकित्सकों ने जमकर तालियां बजाईं। जब उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे हड़ताल समाप्त करने का मीठा वादा करें तो चिकित्सकों ने इस पर हामी भर दी। शाम 5.40 बजे इस मुलाकात के समाप्त होने के तकरीबन तीन घंटे बाद हड़ताल समाप्त होने की औपचारिक घोषणा कर दी गई।

शर्मिंदगी का सबब

तमिलनाडु में सत्ताधारी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब नगर प्रशासन, ग्रामीण विकास और विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री एसपी वेलुमणि ने प्रदेश में जल संकट की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ये खबरें बनावटी हैं। यह खबर उस समय आई जब राज्य सरकार कह चुकी थी कि वह जलापूर्ति से जुड़े मुद्दों की निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन कर रही है। बाद में वेलुमणि अपनी बात से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की ताकि प्रदेश में जल संकट को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।

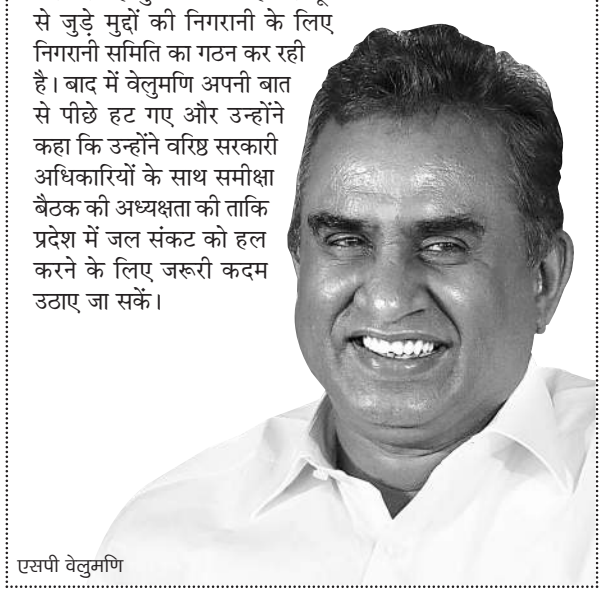

एसपी वेलुमणि

आपका पक्ष

आर्थिक समानता हो मुख्य लक्ष्य

सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक पांच खरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। देश के लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन अगर राज्य सामूहिक रूप से प्रयास करें तो देश की अर्थव्यवस्था 5,000 खरब डॉलर की काबिलियत रखती है। भारत सरकार ने देश के समक्ष एक आशावादी लक्ष्य रखा है। अगर वर्तमान में अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था 2.6 खरब डॉलर की है। जब यह आंकड़ा पढ़ने को मिलता है तब देश के राजनेता और देशवासी भारतीय अर्थव्यवस्था की गुणगान करने लगते हैं। इसके विपरीत जब देश के प्रति व्यक्ति आय की आंकड़ों की बात आती है तब भारत पहले 100 देशों में भी नहीं आता है क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,964 अमेरिकी डॉलर की है। इस मामले में देश 142वें स्थान पर है। इस विरोधाभासी आंकड़े से यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत एक अमीर देश है लेकिन बढ़ती आबादी के कारण यहां गरीब लोग रहते हैं तथा देश में आर्थिक असमानता चरम सीमा पर है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था 5 खरब डॉलर के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए तभी 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था आम नागरिक के लिए फायदेमंद साबित होगी। कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधारों के लिए भारत सरकार को ढांचागत सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है जो अच्छी पहल है। देश में कृषि क्षेत्र में वर्ष 2018-2019 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन जब तक किसानों को उनके परिश्रम के मुताबिक दाम नहीं मिल पाएगा तब तक उनके साथ न्याय नहीं हो सकेगा। आज भी किसान की आय निम्न स्तर पर है। इसलिए प्रतिवर्ष 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। केवल महाराष्ट्र में 808 किसानों ने आत्महत्या की है। देश के किसान, मजदूर और आम आदमी की आय देश में संतोषजनक नहीं है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के 5 खरब डॉलर के लक्ष्य का फायदा हर देशवासी को भी होना चाहिए और आर्थिक समानता प्रस्थापित होनी चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

सरकार का वर्ष 2024 तक अर्थव्यवस्था को पांच खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है

एक देश एक समान बिजली दर हो

सरकार को बिजली की उचित कीमत निर्धारित करनी चाहिए। हर राज्य में बिजली दर अलग-अलग है। दिल्ली और नोएडा में बिजली दर की तुलना करें तो दिल्ली के मुकाबले नोएडा में बिजली दर दोगुनी है। दिल्ली में 200 यूनिट तक प्रति यूनिट एक रुपये है जबकि नोएडा में 4.90 रुपये प्रति यूनिट है। दिल्ली में 400 यूनिट पर बिजली दर 2.50 रुपये है तथा नोएडा में 6.20 रुपये है। वर्तमान में बिजली दरों में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में एक तरफ जहां मांग से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है, वहीं बिजली दर बढ़ाने की कवायद की जा रही है। सरकार को पूरे देश में एक देश एक समान बिजली दर व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।